नई पहचान मुख्यमंत्री ने शहर में की घोषणाएं, करोड़ों की विभिन्न परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण

जबलपुर को फर्नीचर क्लस्टर, बड़ा जू, मेट्रोपॉलिटन सिटी की सौगात

नवभारत,जबलपुर। इंदौर, भोपाल, उज्जैन के बाद अब जबलपुर को एक साल के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, ये मेरा संकल्प है। जबलपुर में फर्नीचर क्लस्टर की अपार संभावनाएं हैं इसलिए जबलपुर में फर्नीचर क्लस्टर जल्द स्थापित किया जाएगा जिससे यहां के फर्नीचर कारीगरों को रोजगार मिलेगा और देश विदेश में फर्नीचर निर्यात करने का शहर एक मुख्य केंद्र बनेगा। जबलपुर के मदनमहल के पास एक बड़ा जू बनाया जाएगा। एम्स की तर्ज पर मेडिकल विश्वविद्यालय को विकसित किया जाएगा।

ये सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को कीं। मौका था घंटाघर स्थित गीता भवन में आयोजित विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह का। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक कर 362.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौंदा, ललपुर व तेवर में बने तीन बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री की सौगात दी। वहीं गुरंदी में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पक्के मत्स्य विक्रय केन्द्र का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कार्यक्रम के दौरान ई.सिटी बस का शुभारंभ किया तथा पीएम स्वानिधि के 500 हितग्राहियों को डिजीटल कार्ड प्रदान किए।

सांदिपनी स्कूलों की मिली सौगात

कार्यक्रम के दौरान विधायक अभिलाष पांडे ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सांदिपनी स्कूल की सौगात दी जाए जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायक को सौगात देकर कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सांदिपनी स्कूल खोला जाएगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से भी कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सांदिपनी स्कूल खोला जाएगा। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहाणी, अभिलाष पांडे, संतोष बरकड़े, नीरज सिंह, सुशील तिवारी, सांसद आशीष दुबे, एसपी संपत उपाध्याय, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोंटिया, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज,नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोंटिया , भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

आकाशवाणी को किया पीएम ने जिंदा

इस दौरान सीएम ने ये भी कहा कि दूरदर्शन, आकाशवाणी को पुरानी पीढ़ी ही जान रही है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से आकाशवाणी को

नई पीढ़ी के सामने जिंदा किया है।

जबलपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है:महापौर

गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व, मार्गदर्शन और विजन के अनुरूप जबलपुर में विकास कार्यों को तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत सीवेज नेटवर्क हर घर नर्मदा जल पहुंचाने सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ है जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री के करकमलों से होना शहर के लिए गौरव का विषय है।

जबलपुर विकास का नया मॉडल बन रहा है : सांसद आशीष दुबे

सांसद आशीष दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को प्रदेश में धरातल पर उतारने का कार्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष लाभ जबलपुर सहित पूरे प्रदेश को मिल रहा है।

> **कांग्रेसियों ने हमेशा से किया है बंटवारा : मुख्यमंत्री**
>
> गीता भवन में आयोजित लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और दो टूक कहा कि देश में कांग्रेस सिमटते जा रही है करीब 80 प्रतिशत इलाकों में भाजपा और एनडीए की चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा से बंटवारा ही किया है चाहे वो समाज का हो या फिर धर्म का। जबकि प्रधासनमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम को एक करने का भाव सभी के सामने पेश किया है।

सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मंत्र के साथ करें काम : सीएम

अज्ञात मृतकों की पहचान करने में मप्र बना देश का पहला राज्य, मुख्यमंत्री ने किया थाना भवन व पुलिस आवास का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मंत्र के साथ समर्पित होकर काम करे। यही सच्ची समाज सेवा है यही जनता की सेवा है। देश में जब भी पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग की बात आए तो हमारी संस्कारधानी जबलपुर पुलिस का नाम सबसे पहले आए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि पुलिसिंग की बेहतरी के लिए तकनीक के सदुपयोग के सद्परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल ऑटोमेडेट फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ;एनएएफआईएस के माध्यम से 16 लाख से अधिक फिंगर प्रिंट डेटाबेस का उपयोग करके 12 सौ से अधिक पेंचीदा मामलों को तत्परता से सुलझाया गया है। वहीं एनएएफआईएस से अज्ञात मृतकों की पहचान स्थापित करने के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बना है। इसी प्रकार ई.समन प्रणाली के माध्यम से 36 लाख से अधिक समन और वारंट तामील कराए जा चुके हैं। ई.साक्ष्य पोर्टल पर 2 लाख 30 हजार से अधिक डिजिटल सबूत दर्ज किए जा चुके हैं।

शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा लगभग 28 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुलिस अधोसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घमापुर थाना परिसर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 22 करोड़ 57 लाख 92 हजार रुपये की लागत से निर्मित आरक्षकों एवं प्रधान आरक्षकों के लिए 96 आवास गृह,

मध्ययप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के तिलवारा में बने 3 करोड़ 21 लाख 80 हजार रुपये की लागत से संभागीय कार्यालय भवन तथा 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक तिलवारा पुलिस थाना भवन का लोकार्पण किया।

नशा मुक्त भारत बनाने में पुलिस की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद को आखरी सलाम करने का श्रेय देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश को है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के पुलिस बल को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र एवं राज्य सरकार वर्ष 2027 तक नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए व्यापक अभियान चला रही हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सेवाए संवेदनशीलता और सुशासन की भावना के साथ कार्य करते हुए जनविश्वास को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया।

महराजपुर में नये थाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन एवं अन्य इकाइयों में मेसए बैरक और आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए जरूरी धनराशि उपलब्ध कराने तथा महाराजपुर में नया थाना बनाने की घोषणा की। उन्होंने सावन एवं आगामी त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा तथा कानून.व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, लोकसभा सांसद आशीष दुबे, आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह , पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ,विधायक अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, नीरज सिंह, डॉ अभिलाष पांडे , संतोष वरकड़े, जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा मुकेश गोंटिया, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर और भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजकुमार पटेल मौजूद रहे।

> **सुशासन का मजबूत आधार है प्रभावी पुलिस व्यवस्था : राकेश सिंह**
>
> लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास का आधार मजबूत कानून .व्यवस्था होती है। आधुनिक थाना भवन और बेहतर अधोसंरचना पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ .साथ जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बदलती तकनीक के अनुरूप अपराध नियंत्रण और जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया। वहीं विशेष पुलिस महानिरीक्षक एवं मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक अनंत कुमार सिंह ने बताया कि जबलपुर जिले में वर्तमान में लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से 564 पुलिस आवास तथा दो नवीन थाना भवनों का निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि निगम अब तक प्रदेश में 40 हजार से अधिक पुलिस आवास तथा दो हजार से अधिक प्रशासनिक भवनों का निर्माण कर चुका है और पुलिस अधोसंरचना के विस्तार का कार्य निरंतर जारी है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने स्मृति चिन्ह के तौर पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा भेंट किया।

मृत अधिकारी के परिवार को पूरा मुआवजा मिले : सुको

- मंडला के उद्यान अधिकारी की मौत के मामले में हाईकोर्ट का फैसला निरस्त
- आय का मूल अधार खोने वाले परिवार को 72 .06 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि के आदेश

जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय से सडक़ दुर्घटना में जान गंवाने वाले मंडला जिले के मोहगांव निवासी उद्यान अधिकारी विश्राम सिंह के परिवार को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्ति के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि घटाने को उचित नहीं माना। कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट, जबलपुर के 10 जुलाई 2024 के फैसले को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट द्वारा गणना की गई 72 लाख 6 हजार 186 रुपये की पूरी क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। इस राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज भी देय होगा।

दरअसल यह मामला सात मार्च 2018 का है। विश्राम सिंह मोटर साइकिल से जा रहे थे, तभी एमपी-09- एफए-1431 नंबर के वाहन ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में वाहन की संलिप्तता, बीमा, चालक की लापरवाही और मृत्यु के तथ्य विवादित नहीं रहे। याचिकाकर्ता सुशीला धुर्वे सहित अन्य अपीलार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव ने पैरवी की। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में अधिवक्ता विनीत मिश्रा, विवेक चौधरी, योगेश गुप्ता व हाईकोर्ट में गोपाल शर्मा और प्रदीप परसाई ने पक्ष रखा। पीड़ित परिवार की ओर से पक्ष रखा। सभी चरणों में क्षतिपूर्ति कम आंके जाने को अनुचित करार दिया गया।

पहले 36 .59 लाख, हाईकोर्ट ने 52 .16 लाख किया

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एमएसीटी जबलपुर ने परिवार को 36 लाख 59 हजार 839 रुपये क्षतिपूर्ति दी थी। बीमा कंपनी की अपील पर हाईकोर्ट ने गणना करते हुए क्षतिपूर्ति 72 लाख 6 हजार 186 रुपये निर्धारित की, लेकिन पारिवारिक पेंशन को आय में शामिल करते हुए नौ का मल्टीप्लायर और बिना भविष्य की संभावनाओं के आधार पर राशि 52 लाख 16 हजार 377 रुपये तक सीमित कर दी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मुआवजे घटाने को अनुचित करार दिया।

बंद पड़े सिग्नलों के मामले में सरकार ने बैठक के मिनट्स किये पेश, अगली सुनवाई 7 सितंबर को

शहर के ट्रैफिक सिग्नलों को संभालेगा नगर निगम

जबलपुर। शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों के रखरखाव की जिम्मेदारी अब जबलपुर नगर निगम को सौंपी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और जबलपुर स्मार्ट सिटी की ओर से प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल के रखरखाव के लिए सालाना 1.50 लाख रुपए नगर निगम को दिए जाएंगे। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने बैठक के पेश किये गये मिनट्स पर गौर करने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय स्पष्ट किया कि जहां भी अतिक्रमण या अन्य बाधाओं के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, वहां आवश्यक कार्रवाई कर उन्हें हटाया जाये, ताकि शहर का यातायात बाधित न हो। मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर वाले सप्ताह में होगी।

उल्लेखनीय है कि यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए कहा कि शहर के कई सिग्नल लंबे समय तक बंद रहने से जाम की समस्या बढ़ी है। कैमरों की निगरानी और ई-चालान व्यवस्था प्रभावित होने से नियम तोड़ने वालों पर अंकुश नहीं लग पा रहा, वहीं शासन को राजस्व की हानि भी हो रही है। याचिका में नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यातायात विभाग के बीच समन्वय के अभाव को समस्या की मूल वजह बताते हुए सभी सिग्नलों को शीघ्र सुचारु करने की मांग की गई थी। जिसके बाद सरकार की ओर से जबलपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के को-चेयरमैन, नगर निगम आयुक्त, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ हुई संयुक्त बैठक के मिनिट्स पेश कर उक्त जानकारी दी गई।

पहल राज्यसभा सांसद तन्खा को सौंपा ज्ञापन

नर्मदा-विंध्य रेल कॉरिडोर को प्राथमिकता देने की मांग

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर। महाकौशल एवं आदिवासी अंचल के रेल विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को उनके जबलपुर स्थित निवास पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट नितिन के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों द्वारा सौंपा गया, जिसमें मंडला जिले सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र की वर्षों पुरानी रेल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिलाने और उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल करने की मांग की गई। यह पहल नारायण सिंह पट्टा के विशेष प्रयासों एवं समन्वय से संपन्न हुई। इस दौरान निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैनसिंह वरकड़े तथा नित्य भारत समाचार पत्र के प्रधान संपादक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से आग्रह किया कि इन जनहित के मुद्दों को राज्यसभा में विशेष उल्लेख अथवा शून्यकाल के माध्यम से प्रमुखता से उठाया जाए, ताकि लंबे समय से लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिल सके ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग नर्मदा-मैकलसुता भोरमदेव रेल कॉरिडोर को लेकर रखी गई। बिलासपुर-पंडरिया-मंडला-ग्वारीघाट के बीच लगभग 230 किलोमीटर के मिसिंग लिंक के लिए तत्काल अपडेटेड ट्रैफिक सर्वे स्वीकृत करने का आग्रह किया गया। साथ ही इस परियोजना को कटघोरा-उसलापुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के साथ समेकित कर राष्ट्रीय महत्व का रेल कॉरिडोर घोषित करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा नर्मदा-विंध्य रेल कॉरिडोर के तहत पेंड्रा-अमरकंटक-डिंडोरी-मंडला-गोरेगांव रेल परियोजना के लिए शीघ्र फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति प्रदान कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि इन दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने से मध्य भारत में रेल संपर्क का नया अध्याय शुरू होगा।

पमरे में शामिल हो मंडला, नैनपुर

ज्ञापन में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर जोन के विस्तार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने यात्रियों की सुविधा, बेहतर रेल संचालन और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन और नैनपुर जंक्शन को पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर जोन के अंतर्गत शामिल करने की मांग की। साथ ही मंडला फोर्ट स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, ताकि भविष्य में लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सके। ज्ञापन में कहा गया कि इससे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट तथा आसपास के जिलों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में रेल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो सकेगा।

> **आदिवासी अंचल का होगा विकास**
>
> प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि ये रेल परियोजनाएं केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आदिवासी अंचलों के सामाजिक-आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन संवर्धन और क्षेत्रीय संतुलित विकास की आधारशिला साबित होंगी। अमरकंटक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भोरमदेव, भेड़ाघाट, रतनपुर सहित अनेक धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को बेहतर रेल संपर्क मिलने से पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी रेल एक्टिविस्ट ने विश्वास जताया कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे को संसद में पूरी मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की अपेक्षा है कि नर्मदा-मैकलसुता भोरमदेव और नर्मदा-विंध्य रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के सर्वे एवं स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो तथा मंडला फोर्ट और नैनपुर जंक्शन को पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर जोन में शामिल कर मंडला फोर्ट को विकसित कोचिंग टर्मिनल का दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे महाकौशल के विकास को नई गति मिल सके।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57